संख्या-2/2015/1437/78-2-2014-73आई.टी./2011

प्रेषक,

जीवेश नन्दन,
प्रमुख सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तर प्रदेश।
3. समस्त ज़िलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

आई.टी. एवं इले. अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक:30 दिसम्बर, 2014

विषय:- मोबाइल-गवर्नेन्स (एम-गवर्नेन्स) के अनुप्रयोग विषयक।

महोदय/महोदया,

प्रदेश में जनसामान्य को उनके द्वार के समीप समस्त सार्वजनिक शासकीय सेवायें पारदर्शिता, विश्वसनीयता एवं कुशलतापूर्वक कम मूल्य पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी का विस्तृत एवं सुनियोजित उपयोग सुनिश्चित करते हुए ई-गवर्नेन्स का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

2. राज्य में व्यापक एवं वृहत मोबाईल फोन उपभोक्ता आधार का संज्ञान रखते हुये मोबाइल-गवर्नेन्स (एम-गवर्नेन्स) के क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा मोबाइल उपकरणों के माध्यम से भी शासकीय सेवाओं की उपलब्धता का निर्णय लिया गया है जिसके अन्तर्गत राज्य के विभिन्न विभागों यथा राजस्व, नगर विकास, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास, परिवहन, वाणिज्य कर इत्यादि के द्वारा विभिन्न सेवाओं से सम्बन्धित सूचनायें यथा आवेदन की अभिस्वीकृति/पावती, सेवा प्रदान करने हेतु निर्धारित समयावधि इत्यादि जनसामान्य को एस.एम.एस. के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं।

3. वर्तमान में एम-गवर्नेन्स के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित स्टेट पोर्टल जिसमें आम जनमानस को 8 विभागों की 26 सेवायें प्रदान की जा रही हैं, के मोबाईल बेस्ड एप्लीकेशन यथा मोबाईल बेस्ड एम.आई.एस./डैसबोर्ड, आवेदन की अद्यतन स्थिति एवं प्रमाणपत्रों के प्रमाणीकरण की सत्यता का विकास किया जा चुका है।

4. उक्त मोबाईल ऐप "यूपी वन" को इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा विकसित राष्ट्रीय मोबाईल ऐप स्टोर पर होस्ट किया गया है जिसकी लिंक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

को उत्तर प्रदेश स्टेट पोर्टल पर भी आम जनमानस के उपयोगार्थ उपलब्ध करा दिया गया है।

5. एम-गवर्नेन्स के पूर्ण रूप से इम्प्लीमेन्टेशन के पश्चात भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर विकसित मोबाईल ऐप स्टोर का उपयोग करते हुए विभिन्न चैनलों यथा एस.एम.एस., आई.वी.आर.एस., मोबाइल ऐप/मोबाइल वेब बेस्ड इन्टरफेस इत्यादि के माध्यम से मोबाइल उपकरणों पर विभिन्न शासकीय सेवाओं जैसे जन्म, मृत्यु, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्रों इत्यादि हेतु आवेदन एवं उनकी अद्यतन स्थिति के अतिरिक्त शासकीय सेवाओं हेतु आवेदन करने, निर्धारित शुल्क का भुगतान आदि सेवायें प्रदान की जा सकेंगी।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने विभाग/जनपद स्तर पर विकसित की गई एप्लीकेशनस को मोबाईल कम्प्लायन्ट बनाते हुए मोबाईल इन्टरफेस विकसित करने हेतु यथावश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ताकि भविष्य में विकसित मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन्स को एक ही स्थान पर होस्ट किया जा सके एवं ई-गवर्नेन्स को अधिकाधिक क्षेत्रों में पहुँचाकर जनमानस को लाभान्वित किया जा सके।

भवदीय,

(जीवेश नन्दन)
प्रमुख सचिव

संख्या:2/2015/1437(1)/78-2-2014 तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव(पी/एन), आई.टी. एवं इले., उ0प्र0 शासन।
2. राज्य समन्वयक, सेण्टर फॉर ई-गवर्नेन्स, उ.प्र.।
3. एस.आई.ओ., एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ।
4. हेड, एस.ई.एम.टी., उत्तर प्रदेश।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महेन्द्र प्रसाद भारती)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in